भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3622
जिसका उत्तर सोमवार 16 मार्च, 2020
26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

कंपनियों का निजीकरण

3622. कुंवर दानिश अलीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में कई कंपनियों का निजीकरण किया गया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी कंपनियों का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार ने अधिकांश हिस्सेदारी की बिक्री और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ सहायक कंपनियों, इकाईयों और संयुक्त उद्यमों सहित 24 सीपीएसईस के निजीकरण के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।

सरकार उन सीपीएसईस के संबंध में रणनीतिक विनिवेश की नीति का अनुसरण करती है, जो 'प्राथमिकता वाले क्षेत्रों' में नहीं हैं। इस प्रयोजन हेतु नीति आयोग को ऐसे सीपीएसईस की (i) राष्ट्रीय सुरक्षा; (ii) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य और (iii) बाजार अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के मापदंडों के आधार पर पहचान करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

सीपीएसईस का रणनीतिक विनिवेश इस मूल आर्थिक सिद्धांत द्वारा मार्गदर्शित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में नहीं बने रहना चाहिए जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और ऐसी कंपनियों की आर्थिक संभावना विभिन्न घटकों जैसे कि पूंजी लगाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा दक्ष प्रबंधन परिपाटियों के कारण रणनीतिक निवेशक के हाथों में संभवतः बेहतर होगी; और इस प्रकार देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

*****